फा. सं. के-11011/30/2023-सीबी-भाग(1)

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

****

4 जुलाई, 2024 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 5वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की 5वीं बैठक 4 जुलाई, 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-क में दी गई है।

2. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे की शुरुआत की।

3. केंद्रीय एजेंडा: राज्य पंचायत संसाधन केन्द्रों (एसपीआरसी) और जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डीपीआरसी) में कम्प्यूटरों के प्रावधान के साथ राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित केंद्रीय एजेंडा को विचार और अनुमोदन के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा गया।

3.1. एजेंडा मद-1: राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) में कंप्यूटरों के प्रावधान के साथ राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण

3.1.1. सीईसी को बताया गया कि पंचायत प्रशिक्षण की जटिलता और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण उपकरण, औजार, संकाय और संसाधन पूल सहित मजबूत संस्थागत क्षमताओं की आवश्यकता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायत प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार सहयोग कर रहा है। संशोधित आरजीएसए

योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसपीआरसी, डीपीआरसी और बीपीआरसी स्थापित करने में सहायता की जा रही है, जिनका उद्देश्य अपने-अपने स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) गतिविधियों, अनुसंधान, विश्लेषण, दस्तावेज़ीकरण और अन्य के संचालन और समन्वय के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करना है। इस योजना में प्रति एसपीआरसी 84 लाख रुपये प्रति वर्ष, प्रति डीपीआरसी 20 लाख रुपये प्रति वर्ष और प्रति बीपीआरसी 4.20 लाख रुपये प्रति वर्ष संकाय और संचालन और रखरखाव सहित आवर्ती लागतों के लिए आवंटित किए जाते हैं।

3.1.2.एसपीआरसी और डीपीआरसी को मोटे तौर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने, संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, अनुसंधान करने और राज्य और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंचायतों को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन पहलों को कई पोर्टल और एप्लिकेशन जैसे ई-ग्रामस्वराज, ईजीएस के साथ पीएफएमएस एकीकरण, जीईएम-ईजीएस एकीकरण, ऑडिट ऑनलाइन, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल, जीपीडीपी डैशबोर्ड, संशोधित पोर्टल पंचायत विकास योजना, स्वामित्व डैशबोर्ड, मेरी पंचायत, पंचायत निर्णय आदि के लॉन्च द्वारा समर्थन दिया गया है। हालाँकि, पोर्टल और अनुप्रयोगों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एस.पी.आर.सी. और डी.पी.आर.सी. में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का अभाव है।

3.1.3.तदनुसार, राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) को एक बार सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि वे 50,000 रुपये प्रति कंप्यूटर की दर से एसपीआरसी में 20 कंप्यूटर और डीपीआरसी में 10 कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर लैब स्थापित कर सकें। तदनुसार, एसपीआरसी को 10 लाख रुपये और डीपीआरसी को 5 लाख रुपये तक की एक बार सहायता प्रदान की जा सकती है, जैसा कि पहले से ही कार्यरत एसपीआरसी और डीपीआरसी के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के तहत प्रस्तावित है।

3.1.4. सीईसी का निर्णय: बेहतर सीबीएंडटी प्रशिक्षण के लिए एसपीआरसी और डीपीआरसी में कंप्यूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए, सीईसी ने विभिन्न

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसपीआरसी और डीपीआरसी में कंप्यूटर लैब और अन्य शिक्षण सहायक उपकरण/उपकरणों के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता के व्यापक आकलन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस तरह किए गए आकलन के आधार पर प्रस्ताव के वित्तीय निहितार्थ पर भी काम किया जाना चाहिए।

4. **राज्य का एजेंडा:**

4.1 सीईसी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु और तेलंगाना की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया। पंचायतों को मजबूत करने और योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सामान्य टिप्पणियां, जैसा कि सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा दूसरी सीईसी बैठक में उल्लेख किया गया था, एमओपीआर के संयुक्त सचिव (सीबी) द्वारा एक बार फिर दोहराई गईं, जो इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई नवीन पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।
ii. कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय राज्यों को कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।
iii. महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए, राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेंगे।
iv. पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
v. राज्यों को अपने आम आदमी पार्टी में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखा, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए ताकि "सरपंच पति" की संस्कृति की जांच की जा सके।
vi. पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई पद्धति को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने की संभावना तलाशी जा सकती है।

vii. वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

viii. राज्यों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की फीडबैक और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना होगा।

ix. राज्यों को जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केन्द्रों (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। 2024-25 के दौरान 100% डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाएगा।

x. राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध धनराशि के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे कर्नाटक परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल को अपनाने के लिए उसका परीक्षण करें।

xii. मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

xiii. प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होकर समापन सत्र के साथ होना चाहिए। इसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

xiv. यह देखा गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर एक्सपोजर विजिट आरजीएसए का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और एक्सपोजर विजिट के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया तथा इन विजिट की योजना संरचित तरीके से बनाई जानी चाहिए। विजिट के दौरान अच्छे अभ्यासों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, फील्ड विजिट की जानी चाहिए तथा सीखे गए सबक पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए तथा अपनी पंचायतों में इसे दोहराने की संभावनाओं और रणनीति के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। योजना में प्रावधान के अनुसार ऐसे विजिट में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

4.2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.2.1 पंचायती राज विभाग के सचिव ने पीआरआई और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी; पीपीसी में प्राथमिक हितधारकों के रूप में एसएचजी और महिलाओं को शामिल करते हुए पंचायत विकास योजना की तैयारी में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएँ और प्रभावी अभिसरण के लिए अंतर-विभागीय प्रशिक्षण; विभिन्न प्रमुख योजनाओं का समुदाय आधारित सामाजिक अंकेक्षण और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए व्हाट्सएप समूह का निर्माण। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण विकास और वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और एसएचजी के सहयोग से हरित द्वीपों की ओर फलों के वृक्षों की पहल और "बेरोजगारी मुक्त अंडमान अभियान" की प्रगतिशील पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों आदि में फलों के पेड़ लगाने के लिए की गई अनूठी पहलों से भी अवगत कराया। जिसका उद्देश्य सभी युवाओं और उत्पादक आयु वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और "बेरोजगारी मुक्त अंडमान" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आजीविका के अवसरों के साथ उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनका मानचित्रण करने के लिए आयु समूहों में बेरोजगार युवाओं का व्यापक सर्वेक्षण करना है और स्थानीय विवादों को ग्राम पंचायत स्तर पर निपटाने के लिए ग्राम पंचायत के भीतर न्याय पंचायतों की संस्था के बारे में भी बताया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों की संख्या कम हुई है।

4.2.2 समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से संसाधन व्यक्तियों को शामिल करना।

(ख) प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन करना ताकि प्रशिक्षण योजना वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर तय की जा सके;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि एक ही व्यक्ति को बार-बार प्रशिक्षित न किया जाए, बल्कि अधिकतम हितधारकों को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाए; न्याय पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए रणनीतियां;

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि द्वीप समूह में बिजली उत्पादन ज्यादातर स्थानीय है और पारंपरिक साधनों पर निर्भर करता है, केंद्र शासित प्रदेश अपनी सभी 70 ग्राम पंचायतों में छत पर सौर ऊर्जाकरण के लिए 'पीएम-सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना' के तहत पंजीकरण के लिए घरों को संतृप्त करने के लिए व्यापक प्रयास कर सकता है।

(ङ) ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने के लिए अनुकरणीय और मापनीय आय सृजन परियोजनाओं की योजना बनाना।

4.2.3 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.52 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और इस टिप्पणी के साथ इसे मंजूरी दी कि केंद्र शासित प्रदेश शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण तथा परस्पर-शिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रदर्शन के लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्राओं के लिए यथासंभव अधिक से अधिक ईआर को शामिल करने का प्रयास कर सकता है।

संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-I में है।

4.3 सिक्किम: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.3.1 पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने पीआरआई और अन्य हितधारकों के लिए सीबीएंडटी की प्रगति, भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) पद्धति के माध्यम से जीपीडीपी की तैयारी, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) आदि पर विस्तृत प्रस्तुति दी। समिति को राज्य के खजाने से एसएनए को आरजीएसए फंड के केंद्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से को समय पर जारी करने में आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिससे आरजीएसए योजना के तहत एएपी 2023-24 के विभिन्न घटकों के तहत प्रगति प्रभावित हुई है। इसके अलावा, राज्य ने अनुरोध किया कि पीबी के निर्माण के लिए लागत मानदंड बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि निर्माण लागत बढ़ गई है। उन्हें इसे उचित ठहराते हुए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई।

4.3.2 सीईसी ने प्रशिक्षण मॉड्यूल में ऑडियो-विजुअल एड्स को शामिल करने का भी सुझाव दिया, ताकि विषय वस्तु को समझना आसान हो और वांछित परिणामों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभावकारिता भी बढ़े। इसके अलावा, समिति ने जागरूकता पैदा करने और आईईसी गतिविधियों में स्थानीय/पारंपरिक बैंड को शामिल करने की सिफारिश की। पॉडकास्ट

का उपयोग एवी एड्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत भी किया जा सकता है।

4.3.3 सिक्किम ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 33.40 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और 25.91 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को इस टिप्पणी के साथ मंजूरी दी कि राज्य को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के भीतर 17 ग्राम पंचायत भवन (कैरीओवर गतिविधि के रूप में अनुमोदित) का निर्माण पूरा करना होगा ताकि राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने स्वयं के पंचायत भवन के लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सिक्किम राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-II में है।

4.4 मिजोरम: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.4.1 सचिव, राज्य पंचायती राज ने पीआरआई और अन्य हितधारकों के लिए सीबीएंडटी की स्थिति, साथ ही स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल के विकास, जीपीडीपी की तैयारी और आय पैदा करने वाली परियोजनाओं की स्थिति आदि पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। समिति को राज्य के खजाने से एसएनए को आरजीएसए फंड के केंद्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से को समय पर जारी करने में आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिससे आरजीएसए योजना के तहत एएपी 2023-24 के विभिन्न घटकों की प्रगति में बाधा आ रही है।

4.4.2 मिजोरम राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 122.99 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 103.11 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

i. **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी):**कम समय में प्रतिभागियों की बढ़ी हुई संख्या को प्रशिक्षण प्रदान करने और स्थानीय भाषा में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण

सामग्री तैयार करने के लिए राज्य की सराहना करते हुए, सीईसी ने विषयगत प्रशिक्षण मॉड्यूल में एवी एड्स को शामिल करने और अधिक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अन्य नवीन तकनीकों का पता लगाने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा, सीईसी ने आरजीएसए कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री विकसित करने के लिए 'प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन' आयोजित करने की सलाह दी।

ii. **ग्राम पंचायत भवन**:राज्य ने प्रस्ताव रखा2024-25 के दौरान 80 नए पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत 313 कैरी ओवर पंचायत भवनों की कोई प्रगति नहीं बताई गई। इसलिए, 2024-25 के दौरान केवल 313 पंचायत भवनों को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 62.60 करोड़ रुपये की राशि कैरी ओवर के रूप में रखी गई।सीईसी ने पीबी निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की और राज्य को ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतवार विस्तृत योजना प्रदान करने और चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के दौरान 313 कैरीओवर पीबी निर्माण का पूरा होना सुनिश्चित करने को कहा।

मिजोरम राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-III में है।

4.5 तमिलनाडु: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.5.1 तमिलनाडु सरकार के पंचायती राज विभाग ने उपलब्धियों, प्रशिक्षण अवसंरचना और राज्य में प्रिंट और सॉफ्ट सामग्री के रूप में उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ राज्य में विकसित शिक्षण वीडियो के साथ-साथ आरजीएसए के अन्य घटकों की प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

4.5.2 तमिलनाडु ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 256.47 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 211.42 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

i. **सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ:** राज्य ने 5 दिन का प्रस्ताव रखा1000 प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) @ 12500 रुपये प्रति प्रतिभागी। हालांकि, समिति ने प्रति प्रतिभागी/दिन 10,000 रुपये के मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

ii. **नये पंचायत भवन का निर्माण**राज्य ने आदिवासी, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 146 इकाइयों के लिए 30.00 लाख रुपये प्रति पंचायत भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और संशोधित आरजीएसए के मानदंडों के अनुसार घटक को मंजूरी दे दी, यानी प्रति पीबी निर्माण 20 लाख रुपये।

iii. **सीएससी सह-स्थान (कैरी ओवर)**राज्य ने 2021-22 से 5.00 लाख रुपये प्रति सीएससी के हिसाब से 460 सीएससी को-लोकेशन का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी, साथ ही राज्य को वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के भीतर इस गतिविधि को पूरा करने की सलाह दी।

iv. **डीपीआरसी का निर्माण:**राज्य ने चेंगलपट्टू, रानीपेट, मयिलादुथुराई, तिरुपथुर और कन्याकुमारी जिलों में 84.20 लाख प्रति डीपीआरसी की दर से 5 डीपीआरसी के निर्माण का प्रस्ताव रखा। समिति ने राज्य प्रतिनिधियों से पूछा कि क्या वे डीपीआरसी निर्माण के लिए प्रस्तावित लागत पर फिर से विचार करना चाहेंगे क्योंकि आरजीएसए के मानदंड 2 करोड़ प्रति डीपीआरसी हैं। हालांकि, राज्य ने उल्लेख किया कि राज्य में इंजीनियरिंग विभाग से अनुमान प्राप्त किए गए थे और प्रस्तावित लागत डीपीआरसी के निर्माण के लिए पर्याप्त थी।

v. **पंचायतों का ई-सक्षमीकरण:**राज्य ने 502 का प्रस्ताव रखासभी ब्लॉकों में 388 बीपीएमयू के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण तथा राज्य में पांच विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के लिए 114 कंप्यूटर और सहायक उपकरण। हालांकि, सीईसी द्वारा घटक को मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि संशोधित आरजीएसए के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

vi. **आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना-आधारित समर्थन:**राज्य ने इस घटक के अंतर्गत दो परियोजनाओं अर्थात पंचायत लर्निंग सेंटर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण आजीविका पार्क को सहायता प्रदान करना प्रस्तावित किया है। समिति ने पंचायत लर्निंग सेंटर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना गतिविधियों पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया, ताकि पंचायत लर्निंग सेंटर से भिन्न नवाचार और विशिष्टता सुनिश्चित की जा सके।

तमिलनाडु राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-IV में है।

4.6 तेलंगाना: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.6.1 सीईसी के अध्यक्ष ने योजना के तहत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, हालांकि, राज्य के वित्त विभाग ने अभी तक केंद्रीय हिस्से के साथ मिलान करने वाला हिस्सा जारी नहीं किया है। राज्य को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने और 2024-25 के दौरान सीबीएंडटी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह दी गई।

4.6.2 तेलंगाना ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 737.18 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 199.01 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

i. **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी):**सीईसी द्वारा तेलंगाना राज्य में 2023-24 के दौरान आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और पाया गया कि पिछले वर्ष लक्षित प्रशिक्षणों में से केवल 0.33% ही हासिल किए गए थे। राज्य द्वारा की गई धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विषयगत प्रशिक्षणों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 233007 से घटाकर 116504 कर दिए गए हैं, जिसके बाद राज्य द्वारा प्रस्तावित राशि 48.76 करोड़ रुपये से घटाकर 24.32 करोड़ कर दी गई है। चूंकि तेलंगाना राज्य में जनवरी 2024 से पंचायत चुनाव होने हैं, इसलिए पंचायत चुनावों के बाद इंडक्शन ट्रेनिंग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
ii. **पंचायत अवसंरचना:**राज्य ने 2024-25 के दौरान 1574 नए पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और पीईएसए क्षेत्र के तहत केवल 17.80 करोड़ रुपये की लागत से 89 नए पीबी निर्माण को मंजूरी दी। इसके अलावा, कैरी ओवर गतिविधि के रूप में 105 पीबी के निर्माण के लिए 8.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

iii. **ई-सक्षमीकरण:** राज्य ने 2024-25 के दौरान 6521 नए कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव रखा है। हालाँकि, 2020-21 के दौरान स्वीकृत 1812 कंप्यूटरों की खरीद के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए, केवल 1812 कंप्यूटर ही खरीदे जा सकेंगे।2024-25 के दौरान कैरी ओवर गतिविधि के रूप में 9.06 करोड़ रुपये की राशि के कंप्यूटरों को मंजूरी दी गई।

तेलंगाना राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-V में है।

अनुबंध-I

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (175 प्रतिभागी)	0.087
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (1444 प्रतिभागी)	0.196
iii	विषयगत प्रशिक्षण (2487 प्रतिभागी)	0.278
lv	विशेष प्रशिक्षण (2203 प्रतिभागी)	0.431
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (104 प्रतिभागी)	0.026
vi	आभासी प्रशिक्षण (1493 प्रतिभागी)	0.006
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**1.02**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (30 प्रतिभागियों के लिए 3 दिनों के लिए)	0.031
ii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (7 दिनों के लिए 40 प्रतिभागियों के लिए)	0.20
iii	पंचायत अध्ययन केन्द्र का विकास (1 पी.एल.सी.)	0.07
iv	पीआरआई के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) (5 दिनों के लिए 140@10,000)	0.70
	सीबीएंडटी का उप-योग	**1.00**
	कुल सीबीएंडटी (1+2)	**2.02**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	2 डीपीआरसी के लिए डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष)	0.4
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.00052
iv	7 बीपीआरसी के लिए बीपीआरसी आवर्ती लागत	0.294
v	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये	0.00397

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
	पर व्यवस्था	
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**1.538**
4	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.216
iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (7 बीपीएमयू)	0.336
	कुल पीएमयू	**0.816**
	उप योग (क्रमांक 1 से 4)	**4.374**
5	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**0.087**
6	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**0.065**
	कुल योजना का आकार	**4.527**

अनुबंध- II

सिक्किम राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I	ईआर के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (1274 प्रतिभागी)	0.96
Ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (2727 प्रतिभागी)	0.92
Iii	विषयगत प्रशिक्षण (5783 प्रतिभागी)	1.38
Iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (12480 प्रतिभागी)	3.76
V	कोई अन्य प्रशिक्षण (550 प्रतिभागी)	0.66
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**7.68**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता (आईएसओ प्रमाणन के लिए 199 जीपी @20,000/-)	0.398
Ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (500 प्रतिभागी) @ 3500/- 5 दिनों के लिए	0.875
Iii	राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट (211 प्रतिभागी) @ 5000/- 7 दिनों के लिए	0.738
Iv	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (20 पीएलसी)	1.40
V	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
Vi	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (270 प्रतिभागी)	0.20
Vii	पंचायती राज संस्थाओं के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (500 प्रतिभागी@10,000, 5 दिन के लिए)	2.50
	सीबीएंडटी का उप-योग	**6.21**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**13.89**
3	**सीबीएंडटी (आवर्ती लागत) के लिए संस्थागत प्रणाली**	
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.806
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (1 डीपीआरसी)	0.20
	सीबीएंडटी (आवर्ती लागत) के लिए कुल लागत संस्थागत तंत्र	**1.00**
4	**सीबीएंडटी के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I	सोरेंग जिले में डीपीआरसी (नया) का निर्माण प्रस्तावित	**2.00**
Ii	पाकयोंग जिले में डीपीआरसी (कैरी फॉरवर्ड) 1 डीपीआरसी का निर्माण	**2.00**
	उप कुल	**4.00**
	सीबीएंडटी के लिए संस्थागत तंत्र की कुल संख्या (3+4)	**5.00**

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
5	**पंचायत भवन के लिए समर्थन**	
I	पंचायत भवन का निर्माण (17 कैरी ओवर)	3.40
Ii	पीबीएस के साथ सीएससी का सह-स्थान (22 नए)	1.10
Iii	पीबी के साथ सीएससी का सह-स्थान (18 कैरी ओवर)	0.90
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**5.40**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.12
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (6 डीपीएमयू)	0.38
	पीएमयू की कुल संख्या	**0.50**
7	***ई*-पंचायतों को सक्षम बनाना**	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (50 जीपी) आगे ले जाएं	0.25
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**0.25**
	1 से 7 तक का उप योग	**25.04**
8.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.50
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.37
	कुल योजना का आकार	**25.91**

अनुबंध- III

मिजोरम राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I	रिफ्रेशर प्रशिक्षण (4170 प्रतिभागी)	2.34
Ii	विषयगत प्रशिक्षण (8,183 प्रतिभागी)	4.72
Iii	विशेष प्रशिक्षण (2502 प्रतिभागी)	1.50
Iv	पंचायत विकास योजना हेतु प्रशिक्षण (4,279 प्रतिभागी)	2.57
V	कोई अन्य प्रशिक्षण (1014 प्रतिभागी)	0.68
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**11.81**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
Ii	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
Iii	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.10
Vi	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 100 प्रतिभागियों के लिए)	0.18
V	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (100 प्रतिभागियों के लिए 7 दिनों के लिए)	0.35
Vi	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (9 जीपी)	0.02
Vii	7 पी.एल.सी. के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पी.एल.सी.) का विकास	0.49
Viii	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक(280 प्रतिभागियों के लिए)	0.35
Ix	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (50 @ रु. 10,000 प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	0.25
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**1.94**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**13.75**
3	**(क) संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण)**	
I	डीपीआरसी का निर्माण (3 नए निर्माण)	6.00
	संस्थागत बुनियादी ढांचा (किराया)	
Iii	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (20 भवन)	0.72
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**6.72**
4	**(ख) संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)**	

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
Ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (11 डीपीआरसी)	2.20
Iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (20 बीपीआरसी)	0.84
Iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.0072
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**3.88**
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का कुल योग (3+4)	**10.6**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन**	
I	पंचायत भवन का निर्माण (313 कैरीओवर)	62.60
Ii	पीबी के साथ सीएससी का सह-स्थान - (98 कैरीओवर)	4.90
Iii	पीबी के साथ सीएससी का सह-स्थान - (50 नए)	2.50
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**70.00**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (11 डीपीएमयू)	1.19
Iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (20 बीपीएमयू)	0.96
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.41**
7	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)(573 यूनिट) कैरीओवर	2.87
	पंचायतों की ई-सक्षमता की कुल संख्या	**2.87**
	उप-योग (क्रमांक 1 से 7)	**99.63**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	1.99
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.49
	कुल योजना का आकार	**103.11 करोड़.**

अनुबंध- IV

तमिलनाडु राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी)**	
I	सामान्य अभिमुखीकरण(9770 प्रतिभागी)	2.21
Ii	पंचायत विकास योजना (29620 प्रतिभागी)	4.74
Iii	विषयगत प्रशिक्षण-(56192प्रतिभागी)	12.62
Iv	विशेष प्रशिक्षण(41740प्रतिभागी)	11.12
V	कोई अन्य प्रशिक्षण (108272 प्रतिभागी)	41.74
	सीबीएंडटी का कुल योग	**72.43**
2	**सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियां**	
I	जीपीडीपी (500 जीपी) के लिए सहायता	1.00
Ii	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
Iii	प्रशिक्षण सामग्री विकास	0.10
Iv	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (2500)	2.625
V	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (2000)	5.00
Vi	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (36)	2.52
Vii	सीबीएंडटी का मूल्यांकन	0.10
Viii	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (500)	0.625
Ix	नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम(1000)	5.00
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**17.07**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I	डीपीआरसी निर्माण (5डीपीआरसी)	4.21
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**4.21**
4	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)**	
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
Ii	37 डीपीआरसी के लिए डीपीआरसी आवर्ती लागत	6.66
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराये पर लेना	0.37

	स्तर (जिला स्तर पर प्रशिक्षण का 1%)	
iv	किराये के भवन में बीपीआरसी	6.98
V	388 बीपीआरसी के लिए बीपीआरसी आवर्ती लागत	16.29
Vi	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.17
	आवर्ती लागत का कुल योग	**31.31**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (37 डीपीएमयू)	3.98
Iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (388 बीपीएमयू)	18.62
	पीएमयू की कुल संख्या	**22.87**
6	**पंचायत भवनों और सीएससी सह-स्थान के लिए समर्थन**	
I	नए पीबी(146पीबी) का निर्माण	29.20
Ii	पंचायत भवन के साथ सीएससी (460) का सह-स्थान (2021-22 से आगे बढ़ाया गया)	23.00
	पीआई का कुल	**52.20**
7	**सैटकॉम / आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
I	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1)	1.00
Ii	सैटकॉम में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति (4)	0.24
Iii	वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का तरीका (वर्ष 2023-24 से 36 @1.5 लाख प्रति व्यक्ति आगे बढ़ाया जाएगा)	0.54
Iv	वैकल्पिक प्रौद्योगिकी (160 @1.5 लाख प्रत्येक)	2.4
	दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं की कुल संख्या	**4.18**
	उप-योग (क्रमांक 1 से 7)	**204.28**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	4.08
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.06
	कुल योजना का आकार	**211.42**

अनुबंध- V

तेलंगाना राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**	
I	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (133090 प्रतिभागी)	20.51
Ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (1242 प्रतिभागी)	0.93
Iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (116504 प्रतिभागी)	24.38
Iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (8220 प्रतिभागी)	3.41
V	कोई अन्य प्रशिक्षण (11172 प्रतिभागी)	6.06
	सीबीएंडटी का कुल योग	**55.29**
2	**सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियां**	
I	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (160 जीपी)	0.32
Ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (500 प्रतिभागी)	0.52
Iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (608 प्रतिभागी)	1.52
Iv	पंचायत अध्ययन केन्द्र का विकास (9 इकाई)	0.63
V	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (250 प्रतिभागी)	0.31
Vi	नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (200 प्रतिभागी)	1.00
Vii	टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री	0.40
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**4.70**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
मैं	डी.पी.आर.सी. का निर्माण (23 नये)	46.00
द्वितीय	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.15
तृतीय	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना (32)	0.63
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**46.78**
4	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)**	
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
Ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (9 डीपीआरसी)	1.80
	आवर्ती लागत का कुल योग	**2.64**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई**	

I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (4 एसपीएमयू)	0.264
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (32 डीपीएमयू)	3.456
Iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (539 BPMU)	25.87
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की कुल संख्या	**29.59**
6	**पंचायत भवनों के लिए समर्थन**	
I	पेसा क्षेत्र में पीबी का निर्माण (89 नए)	17.80
Ii	पीबी का निर्माण (105 कैरी फॉरवर्ड)	8.48
Iii	पेसा क्षेत्र में सीएससी सह-स्थान (89 नए)	4.45
Iv	सीएससी सह-स्थान, (60 कैरी फॉरवर्ड)	3.00
	पंचायत भवनों के लिए कुल सहायता	**33.73**
7	**पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता**	
I	राज्य समन्वयक (1)	0.072
Ii	जिला समन्वयक (9)	0.324
Iii	ब्लॉक समन्वयक (33)	0.99
Iv	ग्राम सभा मोबिलाइज़र/जीपी (1282)	6.15
V	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (220)	0.33
	पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता की कुल राशि	**7.86**
8	**ई-सक्षमता**	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (1812 कैरी ओवर)	9.06
Ii	आवेदन का स्थानीय भाषा में अनुवाद (1)	0.02
	ई-सक्षमीकरण गतिविधियों की कुल संख्या	**9.08**
9	**सैटकॉम/आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
I	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1)	1.00
Ii	सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल (108 मंडल/ब्लॉक)	1.62
	दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं की कुल संख्या	**2.62**
	उप-योग (क्रमांक 1 से 9)	**192.29**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.84
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.88
	कुल योजना का आकार	**199.01**

अनुबंध-क

4 जुलाई, 2024 को आयोजित संशोधित आरजीएसए की पांचवीं सीईसी बैठक के प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर):

क्रम सं.	**नाम**	**पद का नाम**
1	श्री विवेक भारद्वाज	सचिव
2	श्री विकास आनंद	संयुक्त सचिव
3	श्री योगिन्दर सिंह	उप सचिव, एमओपीआर
4	श्री तारा चंदर	अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
5	श्री सोनू कुमार	अनुभाग अधिकारी, पंचायती राज मंत्रालय
6	सुश्री पियाली रॉय	परामर्शदाता, एमओपीआर
7	सुश्री रुचि यादव	परामर्शदाता, एमओपीआर
8	श्री विजय सिंह	परामर्शदाता, एमओपीआर
9	सुश्री किरण ज्योति	परामर्शदाता, एमओपीआर

लाइन मंत्रालय की सूची:

क्रम सं.	**नाम**	**पद का नाम**
1	विनोद कुरियाकोरे	सीएससी ई गवर्नेंस सेवाएं भारत

राज्यों के प्रतिभागियों की सूची:

क्रम सं.	**नाम**	**पद का नाम**
1	श्री अर्जुन शर्मा	सचिव, पीआरडी, अंडमान एवं निकोबार
2	श्री मोहम्मद युनुस एम	एसएनओ, आरजीएसए, अंडमान एवं निकोबार
3	सुश्री टेरेसी वनलालहरुआली,	सचिव, पीआरडी, मिजोरम
4	सुश्री रीता लालनुनमावलीपचुआउ,	निदेशक, मिजोरम
5	सुश्री लालचाविमाविया,	संयुक्त सचिव एवं एसएनओ आरजीएसए, मिजोरम
6	श्री झोन लालनुसांगा,	एसपीएम, आरजीएसए, मिजोरम
7	डॉ. सुश्री डावंगलियानी	एसोसिएट प्रोफेसर (ए), मिजोरम

क्रम सं.	नाम	पद का नाम
8	डॉ. खुआंगथांसंगापाखुंगटे	एसोसिएट प्रोफेसर (पीपी), मिजोरम
9	श्री अनंधन	प्रधान सचिव, सिक्किम
10	श्री तेनजिंगडेन्जोंग्पा	निदेशक, पीआरडी, सिक्किम
11	श्री बिशाल मुखिया	निदेशक, एसआईआरडी, सिक्किम
12	सुश्री के. निखिला, आईएएस,	मुख्य सचिव कार्यकारी अधिकारी, टीजीआईआरडी
१३	श्री बी. शफीउल्लाह, आईएफएस,	विशेष आयुक्त, पीआर एंड आरई
14	श्री पी. रामा राव,	राज्य परामर्शदाता, सेवानिवृत्त उपायुक्त, पीआर एंड आरई, तेलंगाना
15	श्री आर. स्टीवन नील,	केंद्र प्रमुख, सीडीपी&ए, टीजीएसआईआरडी
16	श्री. गगनदीप सिंह बेदी, आईएएस	अपर मुख्य सचिव
17	श्रीमती वी. शोभना, आईएएस,	आयुक्त (प्रशिक्षण), आरडी एंड पीआर
18	श्री पी. पोन्नैया, आईएएस,	निदेशक, आरडी एंड पीआर
19	श्रीमती बी. श्री देवी	संयुक्त निदेशक, आरडी एंड पीआर
20	श्री. जे. नकीरन	संयुक्त निदेशक, एसआईआरडी&पीआर
21	श्री एम. अलविन देवा अरासु	राज्य समन्वयक, आरडी&पीआर